

प्रेषक,

आर० डी० पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 28 जनवरी, 2008

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता/कार्यावधि बढ़ाया जाना ।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-21/xxxvi(1)-दो/2007-10एक(2)/05,दिनांक 28.02.07 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए स्वीकृत सभी अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन,यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 01-03-08 से 28-02-09 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त न्यायालय के लिए स्वीकृत कार्यालय व्यय के अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है । उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या-13-एक(2)/छत्तीस(1)/2005-10-एक(2)/05,दिनांक 29-10-2005 द्वारा किया गया था ।

2- उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संगम की सेवा नियमावली से अवधारित होगी ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला एवं सेशन न्यायाधीश-00" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय झाप संख्या-ए०-1-1270/76-दस,दिनांक 20 जुलाई,1968 सपठित कार्यालय झाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92,दिनांक 7-11-92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त),द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधित्वित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर० डी० पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 25/xxxvi(1)/2008-10 एक(2)-05/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड,माजरा, देहरादून ।
- 2- समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,उत्तराखण्ड ।
- 3- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
- 4- वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।